भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 813
दिनांक 24 जुलाई, 2025

अंडमान और निकोबार क्षेत्र में कच्चे तेल और हाइड्रोकार्बन भंडार अन्वेषण योजना

813. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वेः
श्री एम. के. राघवनः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अंडमान-निकोबार बेसिन में संभावित हाइड्रोकार्बन भंडारों की खोज को भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के कार्यनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और यदि हों, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह या आसपास के अपतटीय क्षेत्रों में कच्चे तेल या हाइड्रोकार्बन भंडारों की उपस्थिति के बारे में ब्यौरा क्या है, और अनुमानित भंडार और प्रारंभिक अन्वेषण सर्वेक्षणों के परिणाम क्या हैं;

(ग) क्या 2020 में ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) द्वारा किए गए गहन अंडमान अपतटीय सर्वेक्षण के दौरान विशिष्ट क्षेत्रों में तेल और गैस की उपस्थिति के प्राथमिक संकेत मिले थे और क्या उन क्षेत्रों में ड्रिलिंग की अनुमति दी गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस क्षेत्र से कच्चे तेल के वाणिज्यिक अन्वेषण या निष्कर्षण के लिए कोई योजना शुरू की है और यदि हाँ, तो ऐसे अन्वेषण कार्यकलापों की समय-सीमा और इसमें शामिल एजेंसियों या भागीदारों सहित ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ओपन एकरेज लाइसेंसिंग नीति (ओएएलपी) और हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी) के अंतर्गत राष्ट्रीय डेटा रिपोजिटरी (एनडीआर) से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करने हेतु किया जा सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अंडमान क्षेत्र में अब तक किन ब्लॉकों के लिए निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(च) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने 2013-14 के दौरान अंडमान क्षेत्र में छह कुओं की खुदाई की थी, लेकिन उसे व्यावसायिक सफलता नहीं मिली और क्या 2020 के बाद सरकार द्वारा

अपनाई गई नई रणनीति, जैसे उथले जलक्षेत्रों में अन्वेषण, पूर्व की विफलताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (च) वर्ष 2014 के बाद, भारत में कई बड़े सुधार और नीतिगत बदलाव हुए हैं, जिन्होंने अन्वेषण और उत्पादन (ईएंडपी) परिदृश्य को एक नवीन रूप दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक वर्ष 2015 में उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) व्यवस्था से अधिक व्यवसाय-अनुकूल राजस्व हिस्सेदारी संविदा (आरएससी) मॉडल में परिवर्तन था। वर्ष 2022 में, सरकार ने पहले "निषिद्ध" घोषित क्षेत्रों को खोलकर एक कार्यनीतिक कदम उठाया, जिससे अन्वेषण की गुंजाइश बढ़ गई। इसके अलावा, वर्ष 2016 से वर्ष 2025 तक, सरकार ने डेटा-संचालित अन्वेषण पर ज़ोर दिया, जिसमें तलछटी बेसिन डेटा उत्पादन, राष्ट्रीय डेटा रिपॉजिटरी (एनडीआर) का विस्तार करना और वर्ष 2024 में एक स्ट्रेटीग्राफिक कूप वेधन अभियान का शुभारंभ करना, शामिल है। इन प्रयासों की परिणति तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 में ऐतिहासिक संशोधन के रूप में हुई, जिसे वर्ष 2025 में संसद द्वारा पारित किया गया।

संरचनात्मक सुधारों के अलावा, भारत सरकार ने वर्ष 2016 में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और अनुज्ञप्ति नीति (एचईएलपी) और इसकी प्रमुख पहल, खुला रकबा अनुज्ञप्ति कार्यक्रम (ओएएलपी) जैसी कई सक्षमकारी नीतियाँ प्रस्तुत कीं। अन्य सहायक उपायों में प्राकृतिक गैस के लिए विपणन और मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता प्रदान करना, खोजे गए लघु क्षेत्र नीति (2018), तलछटी बेसिन वर्गीकरण और वर्ष 2022 में कच्चे तेल के विपणन को नियंत्रणमुक्त करने के साथ वर्ष 2019 में राजकोषीय और संविदात्मक छूट, शामिल था। इन पहलों का उद्देश्य निवेश आकर्षित करना, नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाना और घरेलू हाइड्रोकार्बन उत्पादन को बढ़ावा देना था।

इन समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप, वर्तमान अन्वेषण क्षेत्रों का 80% से अधिक वर्ष 2015 के बाद आवंटित किया गया और चौदह नई हाइड्रोकार्बन खोजें की गईं। एनडीआर के माध्यम से बढ़ी हुई डेटा उपलब्धता ने हाल के बोली दौरों में गहरे अपतटीय ब्लॉकों में अधिक रुचि पैदा की है। खुला रकबा बोली दौरों में भागीदारी के स्तर में भी सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। ओएएलपी और खोजे गए लघु क्षेत्र नीति के अन्तर्गत आवंटित क्षेत्रों में परीक्षण उत्पादन शुरू हो गया है और यह प्रवृत्ति वाणिज्यिक प्रचालन के लिए एक आशाजनक भविष्य का संकेत देती है। ये उपलब्धियाँ घरेलू अन्वेषण को बढ़ाने, निजी निवेश को आकर्षित करने और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा की ओर बढ़ने के लिए भारत के सुदृढ़ नीतिगत प्रयास और कार्यनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाती हैं।

इसके अलावा, अंडमान-निकोबार (एएन) बेसिन में कच्चे तेल और हाइड्रोकार्बन भंडारों की खोज और पहचान करने की दिशा में सरकार निरंतर उपाय कर रही है जिससे वे देश की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा में योगदान दे सकें और आयात पर निर्भरता कम हो सके। भारत के हाइड्रोकार्बन संसाधन आकलन अध्ययन (एचआरएएस) के अनुसार, एएन बेसिन में 371 मिलियन मीट्रिक टन तेल समतुल्य (एमएमटीओई) हाइड्रोकार्बन संसाधन मौजूद हैं। एचआरएएस 2017 के बाद, भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (अंडमान अपतटीय क्षेत्र सहित) के लगभग 80,000 लाइन किलोमीटर में 2-आयामी (2डी) ब्रॉडबैंड भूकंपीय सर्वेक्षण वर्ष 2024 में पूरा हो चुका है। इससे संभावित हाइड्रोकार्बन भंडारों की पहचान के लिए आवश्यक उप-सतही डेटा प्राप्त करने में मदद मिली है। सरकार ने ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) के माध्यम से वर्ष 2021-22 के दौरान गहरे अंडमान अपतटीय सर्वेक्षण में कुल 22,555 लाइन किलोमीटर (एलकेएम) 2डी भूकंपीय डेटा भी प्राप्त किया है। विदेशी प्रचालक सहित अन्वेषण एवं उत्पादन (ईएंडपी) कम्पनियों को ब्लॉक चुनने और उसके बाद ओएएलपी बोली दौर में रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)/या बोलियाँ प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रीय डेटा रिपॉजिटरी (एनडीआर) पर उपलब्ध ईएंडपी डेटा तक पहुँच प्राप्त है। खुला रकबा अनुज्ञप्ति कार्यक्रम (ओएएलपी) बोली दौर के अन्तर्गत मेसर्स ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) और मेसर्स ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) को चार ब्लॉक प्रदान किए गए हैं।

ओएनजीसी ने वर्ष 2013-14 के दौरान एएन बेसिन में किसी कूप का वेधन नहीं किया है। तथापि, बिना किसी व्यावसायिक सफलता के वर्ष 2011-13 के दौरान छः कूप वेधित किए गए। सरकार नीतिगत प्रोत्साहनों की एक श्रृंखला के माध्यम से चुनौतीपूर्ण अपतटीय क्षेत्रों (जिसमें एएन बेसिन का उथला जल क्षेत्र शामिल हैं) में सक्रियता से अन्वेषण को बढ़ावा दे रही है, जिसमें अनुलग्नक-1 में सूचीबद्ध डेटा अधिग्रहण भी शामिल है। नए डेटा अधिग्रहण और उसकी व्याख्या के आधार पर, ओआईएल और ओएनजीसी ने एएन बेसिन में व्यापक वेधन अभियान चलाए हैं।

*****

अनुलग्नक-1

1. अपतटीय क्षेत्र में लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर (एसकेएम) 'निषिद्ध' क्षेत्र, जो दशकों से अन्वेषण के लिए अवरुद्ध था, को सितंबर, 2022 में अन्वेषण एवं उत्पादन कार्यकलापों के लिए खोल दिया गया था।

2. भारत सरकार ने ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) के माध्यम से वर्ष 2021-22 के दौरान गहरे अंडमान अपतटीय सर्वेक्षण में कुल 22,555 लाइन किलोमीटर (एलकेएम) का द्वि-आयामी (2डी) भूकंपीय डेटा प्राप्त किया है।

3. अन्वेषण के वर्तमान चरण के लिए, 20,000 वर्ग किलोमीटर तक के बड़े ब्लॉकों को चिह्नित किया गया है, जो इस सीमांत बेसिन में संसाधन के मूल्यांकन हेतु एक महत्वाकांक्षी और कुशल दृष्टिकोण को दर्शाता है।

4. 7 वर्ष की अवधि का विस्तारित अन्वेषण चरण,

5. निम्न राजस्व बिंदु (एलआरपी) दर पर राजस्व हिस्सेदारी के लिए 7 वर्ष तक की स्थिरीकरण अवधि,

6. उप-व्यावसायिक खोजों के लिए तीन वर्ष की अवधारण अवधि,

7. बोली लगाने से पहले कंसोर्टियम में परिवर्तन,

8. निःशुल्क बुनियादी डेटा पैकेज, कम बोली बांड, तर्कसंगत प्रचालक अनुभव

9. केवल 2डी और त्रि-आयामी (3डी) भूकंपीय पर बोली लगाना, जिसमें 10 अंकों का ऑरिजिनेटर इंसेंटिव प्रोत्साहन शामिल है।